

प्रेषक,

भास्करानन्द,

राविव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

देहरादून।

राजस्व अनुभाग-2

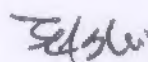
देहरादून: दिनांक 12 अक्टूबर 2013

विषय:-ग्राम निरंजनपुर, जनपद देहरादून में क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय की 0.600 है० भूमि जे०एन०एन०यू०आर०एम० के सब मिशन बी०एस०यू०पी० के अन्तर्गत ब्रह्मपुरी फेज-1 एवं फेज-2 के क्रियान्वयन हेतु नगर निगम, देहरादून को आवंटित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र संख्या-359/डी०एल०आर०सी०-2012-XII-A-14 2011-14 दिनांक 18.05.2012 के सन्दर्भ में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल, ग्राम निरंजनपुर, जनपद देहरादून में क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय हेतु वर्ष 1988 में जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा आवंटित 0.8090 है० भूमि का समयान्तर्गत विनिर्दिष्ट प्रयोजन पूर्ण नहीं किये जाने के कारण इस भूमि में से 0.600 है० भूमि का आवंटन निरस्त करते हुए उक्त 0.600 है० भूमि, भारत सरकार द्वारा संचालित जे०एन०एन०यू०आर०एम० परियोजना के सब मिशन बी०एस०यू०पी० के अन्तर्गत ब्रह्मपुरी फेज 1 एवं फेज-2 के क्रियान्वयन हेतु नगर निगम, देहरादून द्वारा किये गये अनुरोध तथा नगर विकास विभाग की सहमति के दृष्टिगत, निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन, नगर निगम, देहरादून को नियमानुसार निर्धारित शुल्क पर आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- 1- भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
- 2- जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी है।
- 3- हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिए मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- 4- यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।
- 5- जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।



- 6- जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।
- 7- प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु, तभी अनुमत्त होगा, जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जनपद स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति अनिवार्य रूप से शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

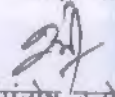
(भास्करानन्द)
सचिव।

पृ०प०संख्या- 305/समदिनांकित/2013

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 4- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 5- मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून।
- 6- निदेशक, एन०आई०सी० सचिवालय।
- 7- प्रगारी गीडिया केन्द्र सचिवालय।
- 8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।